Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

जनवरी (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- कालका से कलेसर तक के पर्वतीय क्षेत्र को तीर्थाटन के रूप में किया जाएगा विकसित 3
- हरियाणा में वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का लिया गया संकल्प 3
- हरियाणा सरकार ने की विभागों के विलय की अधिसूचना जारी 4
- हर हित स्टोर व वीटा बूथ योजना 4
- मुख्यमंत्री ने किया गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की एनिमेशन एवं मल्टीमीडिया लैब का उद्घाटन 5
- इंस्पायर अवॉर्ड स्कीम 5
- महेंद्रगढ़ ज़िले में नांगलमाला से धौली तक नई सड़क निर्माण के लिये ज़मीन खरीद का प्रस्ताव स्वीकृत 6
- हरियाणा के 10 ज़िलों में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की तर्ज पर खोले जाएंगे इनोवेटिव स्किल स्कूल 6
- जी-20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकों की मेजबानी हरियाणा को मिली 7
- हरियाणा में महाराष्ट्र की तर्ज पर काम करेगी यातायात पुलिस 8
- मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत रोगियों को 25 गंभीर बीमारियों के लिये उपलब्ध करवाई जाएगी आर्थिक सहायता 8
- सरस्वती महोत्सव-2023 9
- प्रदेश की सभी एयर-स्ट्रिप्स पर एटीएस और फायर-सिस्टम लगाए जाएंगे 9
- हरियाणा पुलिस और आईआईएम रोहतक के बीच हुआ समझौता ज्ञापन 10
- संस्कृत साहित्यकारों की सम्मान राशि में बढ़ोत्तरी 11
- हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिये लिंक अधिकारी किये नामित 12
- 'हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल' लॉन्च 12
- हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 54वीं बैठक 13
- राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 86 बेटियों को किया जाएगा पुरस्कृत 15
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी की बैठक 15
- गणतंत्र दिवस समारोह के लिये हरियाणा की झाँकी का थीम होगा 'अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव' 15
- इंडो-इजराइल कृषि परियोजना के तहत गिगनाऊ में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ 16
- गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैदियों को मिलेगी तीन महीने तक की छूट 17
- प्रदेश के दो विभूतियाँ पद्म श्री सम्मान के लिये चयनित 18
- दीनबंधु छोटूराम के जयंती समारोह में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएँ की 18
- हरियाणा-सस्केचेवान शैक्षणिक गोलमेज सम्मेलन का हुआ आयोजन 19
- मुख्यमंत्री ने तेजली स्टेडियम के विकास के लिये की 90 करोड़ रुपए की घोषणा 19
- प्रदेश में 33 नए महिला पुलिस थाने और 239 महिला हैल्प डेस्क स्थापित 20
- यूआईईटी के दो छात्रों का स्मार्ट सोलर हब हुआ लॉन्च 20
- हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारी पुलिस पदक से सम्मानित 21
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुप्तिसागर नेचर केयर इंस्टीट्यूट का किया शिलान्यास 21
- कुरुक्षेत्र के किरमिच गाँव से हुई प्रधानमंत्री मोदी की 'मन की बात' कार्यक्रम की शुरुआत 21
- स्वास्थ्य विभाग व हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित 22
- जॉर्जिया और हरियाणा विभिन्न विषयों पर करेंगे सहयोग 23

नोट :

हरियाणा

कालका से कलेसर तक के पर्वतीय क्षेत्र को तीर्थाटन के रूप में किया जाएगा विकसित

चर्चा में क्यों ?

1 जनवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेशवासियों को नववर्ष का तोहफा देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले माता मंत्रादेवी मंदिर से आदिबद्री तक रोप-वे बनाने के साथ-साथ शिवालिक हिल्स के कालका से कलेसर तक के पर्वतीय क्षेत्र को तीर्थाटन के रूप में विकसित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में शिवालिक हिल्स में पंचकुला के कालका से यमुनानगर के कलेसर तक के पर्वतीय क्षेत्र को तीर्थाटन के रूप में विकसित करने के अंतर्गत छोटा तिरलोकपुर, आदिबद्री, लोहगढ़, कपालमोचन, कलेसर इत्यादि शामिल हैं। इसके लिये लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग द्वारा 10 मीटर चौड़ा सड़क मार्ग बनाने की संभावना तलाशी जाएगी।
- इसके अलावा, इस क्षेत्र में साहसिक खेल गतिविधियों जैसे ट्रैकिंग शुरू करने की भी योजना है। सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश में जहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे।
- उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा स्थापित सिख राज की पहली राजधानी लोहगढ़, यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर के शौर्य एवं बलिदान की गाथा को पुनर्जीवित करने के लिये स्मारक की आधारशिला भी रखी। लोहगढ़ को एक मिनी शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सोनीपत ज़िले के खंडा शेरी गाँव से युवाओं को एकत्र कर सेना गठन की शुरुआत की थी और पूरे हरियाणा में युवाओं के साथ दौरा कर एक सेना खड़ी की और लोहगढ़ को सिख राज की पहली राजधानी बनाया। बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लोहगढ़ का क्षेत्र आधा हरियाणा और आधा हिमाचल में पड़ता है।

हरियाणा में वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का लिया गया संकल्प

चर्चा में क्यों ?

31 दिसंबर, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंत्योदय उत्थान वर्ष 2022 के अपने प्रयासों की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज में किसी कारणवश जो वर्ग पिछड़ गए हैं, उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिये वर्ष 2022 को अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया था। अंत्योदय उत्थान के तहत ही नागरिकों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करते हुए 5 एस- शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर ज़ोर दिया गया है।
- उन्होंने बताया कि अंत्योदय आरोग्य वर्ष के अंतर्गत प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी और गरीब व्यत्ति को इलाज के लिये किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नही करना पड़ेगा। इसी विजन के साथ राज्य सरकार ने निरोगी हरियाणा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पहले चरण में प्रदेश के अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि कि वर्ष 2023 एक अन्य मामले में भी बहुत विचारणीय बनने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला भी लिया गया है। हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर चलते हुए प्रदेश में मोटा अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये भरसक प्रयास करेगी।

नोट :

- उन्होंने बताया कि एक ओर जहाँ मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, तो इसकी खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। मोटा अनाज शरीर को पोषण देने और रोगों से ठीक करने की क्षमता के लिये पहचाने जाते हैं। इनमें बड़ी मात्रा में फाइबर, खनिज और प्रोटीन होता है। इसलिये भोजन में मोटा अनाज अवश्य शामिल करना चाहिये और इस प्रकार यह 'आहार ही औषधि'का काम भी करेगा।

हरियाणा सरकार ने की विभागों के विलय की अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों ?

2 जनवरी, 2023 को एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार के उद्देश्य से कुछ विभागों का विलय एवं पुनर्गठन कर दिया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अब नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को विद्युत विभाग के साथ विलय करके नए विभाग का नाम बदलकर 'ऊर्जा विभाग'किया गया है तथा वन एवं वन्य जीव विभाग तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का विलय कर इसका नाम बदलकर 'पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग'किया गया है।
- पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग का पर्यटन विभाग में विलय करके विभाग का नाम बदलकर 'विरासत तथा पर्यटन विभाग'किया गया है तथा उच्चतर शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग का विलय करके नए विभाग का नाम 'उच्चतर शिक्षा विभाग'किया गया है।
- सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग को भंग कर दिया गया है। इस विभाग के कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण व निजी आईटी तथा हारट्रोन को 'उद्योग तथा वाणिज्य विभाग'के दायरे में लाया गया है।
- इसी प्रकार, कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग का विलय सूचना, लोकसंपर्क एवं भाषा विभाग के साथ किया गया है और इसका नाम बदलकर 'सूचना, लोकसंपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग'किया गया है तथा श्रम तथा रोज़गार विभाग के स्थान पर अब 'श्रम विभाग'नाम रखा गया है।
- अनुसूचित जातियाँ तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग का विलय करने के बाद इसका नया नाम 'सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग'किया गया है तथा खेल एवं युवा मामले विभाग के स्थान पर अब इसका नाम 'खेल विभाग'रखा गया है।
- प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 'युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग'नाम से नया विभाग गठित किया है। इसमें कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग और रोज़गार विभाग तथा युवा मामले विभाग का विलय किया गया है।

हर हित स्टोर व वीटा बूथ योजना

चर्चा में क्यों ?

2 जनवरी, 2023 को हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने बताया कि हरियाणा डेयरी फेडरेशन के वीटा बूथ और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज द्वारा राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये वीटा बूथ एवं हर हित स्टोर खोलने की बेहतर योजना क्रियान्वित की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का कोई भी पात्र व्यक्ति हर हित स्टोर खुलवाने का विकल्प चुनता है तो डेयरी फेडरेशन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के युवाओं को प्रतिभूति राशि में भी छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार बिना किसी प्रतिभूति राशि के युवा हर हित स्टोर लेकर आजिविका के लिये स्थायी आमदनी का जरिया बनाकर अपना भविष्य सुखद एवं सुखमय बना सकते हैं।

नोट :

- उन्होंने बताया कि हर हित स्टोर के लिये युवाओं को बैंक ऋण की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हर हित स्टोर खोलने के लिये पात्र व्यक्ति के पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में किराए या खुद का 200 वर्ग फुट का स्थान होना चाहिये। पात्र व्यक्ति की आयु 18 से 55 साल व शैक्षणिक योग्यता केवल दसवीं पास होनी जरूरी है।
- उन्होंने बताया कि वीटा बूथ खोलने के लिये लगभग दो लाख 70 हज़ार रूपए तक लागत आती है। इसमें दुकान के रैक व पैक्ड सामान की लागत भी शामिल होती है। इस स्कीम के तहत हरियाणा एग्रो 15 प्रतिशत और बैंक 85 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाता है।
- राज्य में वीटा बूथ खोलने के लिये 12 बाई 12 वर्ग फुट में वीटा का बूथ स्थापित किया जा सकता है। इसके लिये बीपीएल परिवार से भी प्रतिभूति राशि नहीं ली जाती। अंत्योदय पात्र से केवल दस हज़ार रुपए व सामान्य श्रेणी के आवेदक से सिक्योरिटी के रूप में 50 हज़ार रुपए की राशि ली जाती है। इसके लिये आवेदक की शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास व उम्र कम से कम 18 व अधिकतम 55 साल तक होनी चाहिये।
- सहकारिता मंत्री ने बताया कि हरियाणा डेयरी फेडरेशन के वीटा बूथ और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज द्वारा हर हित स्टोर खोलने का बेहतर विकल्प युवाओं को दिया जा रहा है। एग्रो इंडस्ट्रीज का हर हित स्टोर और वीटा बूथ स्कीम राज्य में काफी लोकप्रिय हो रही है और यह युवाओं के लिये एक महत्त्वाकांक्षी योजना है। हरियाणा सरकार ने 1000 हर हित स्टोर एवं वीटा बूथ खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्यमंत्री ने किया गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की एनिमेशन एवं मल्टीमीडिया लैब का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

5 जनवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के गुरुग्राम ज़िले के गुरुग्राम विश्वविद्यालय की एनिमेशन एवं मल्टीमीडिया लैब का आज उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि रोज़गार की असीम संभावनाओं एवं समय की मांग को देखते हुए गुरुग्राम विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी (एनिमेशन) कोर्स की शुरुआत करना एक सराहनीय पहल है।
- गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों को एनीमेशन एवं मल्टीमीडिया की प्रायोगिक शिक्षा मिल सके, इसी उद्देश्य से अत्याधुनिक कंप्यूटिंग लैब विकसित की गई है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को एनिमेशन फिल्म मेकिंग में 3डी एनिमेटिड डिजिटल ऑब्जेक्ट बनाने की ट्रेनिंग तथा स्पेशल इफेक्ट्स इत्यादि का अभ्यास मिल सकेगा।
- कुलपति ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा तीन वर्षीय बीएससी एनिमेशन व मल्टीमीडिया का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। पाठ्यक्रम में औद्योगिक ज़रूरतों के अनुरूप विद्यार्थियों को हर प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिये नई सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं। इससे विद्यार्थियों को अपने कौशल को निखारने का बेहतर अवसर मिलेगा और वे एनिमेशन व ग्राफिक्स डिजाइनिंग के क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनेंगे।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम से करीब 15 किलोमीटर दूर सेक्टर-87 में 44 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे विश्वविद्यालय के टीचिंग ब्लॉक का डिजिटल माध्यम से शिलान्यास भी किया।

इंस्पायर अवॉर्ड स्कीम

चर्चा में क्यों ?

8 जनवरी, 2023 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिये इंस्पायर अवॉर्ड स्कीम सत्र 2022-23 को लेकर लिस्ट जारी की गई, जिसमें हरियाणा प्रदेश के 329 विद्यार्थियों का चयन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- सरकारी स्कूलों के बच्चों को नवाचर के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष इंस्पायर अवार्ड का आयोजन किया जाता है। इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये बच्चों को आनलाइन निबंधन कराना पड़ता है। फिर बच्चों को ऑनलाइन आइडिया भेजना होता है।
- इंस्पायर मानक अवॉर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है।

नोट :

- इंस्पायर मानक अवॉर्ड योजना के अंतर्गत हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों जैसे - मध्य प्रदेश से 1854 विद्यार्थी, झारखंड से 1657 विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश से 901 विद्यार्थी तथा राजस्थान से 5993 विद्यार्थी चयनित हुए हैं।
- प्रत्येक विद्यार्थी को विज्ञान मॉडल बनाने के लिये दस-दस हज़ार रुपए प्रदान किये जाने हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली की ओर से चयनित विद्यार्थियों को यह अवॉर्ड राशि दी जाएगी।
- नए वैज्ञानिक विचारों को विकसित करने और विज्ञान पर आधारित मॉडलों का निर्माण करने वाले विद्यार्थियों को यह राशि मिलेगी। इस राशि से विद्यार्थी विज्ञान मॉडल तैयार करेंगे। भविष्य में होने वाली ज़िला स्तरीय इंस्पायर मानक मॉडल प्रदर्शनी में उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा।

महेंद्रगढ़ ज़िले में नांगलमाला से धौली तक नई सड़क निर्माण के लिये ज़मीन खरीद का प्रस्ताव स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

11 जनवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में ई-भूमि पोर्टल के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिये ज़मीन खरीद हेतु सचिवों की समिति की बैठक हुई, जिसमें महेंद्रगढ़ ज़िले में नांगलमाला से धौली तक नई सड़क निर्माण के लिये जमीन खरीद के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा, समिति ने फतेहाबाद तथा चरखी दादरी में नई ज़िला जेल के निर्माण से संबंधित 2 प्रोजेक्ट्स को हाई पॉवर लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश की। बैठक में कुल 7 प्रोजेक्ट्स के लिये जमीन खरीद के संबंध में चर्चा की गई।
- मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े संबंधित ज़िला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि अन्य परियोजनाओं के लिये आगामी बैठक से पूर्व भू-मालिकों से उनकी सहमति से भूमि खरीदने के संबंध में दूसरे दौर की बातचीत की जाए। साथ ही, परियोजनाओं के लिये वैकल्पिक साइट की भी तलाश की जाए।
- उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कलेक्टर दरों को और अधिक वास्तविक बनाया जाए, जो भूस्वामियों के साथ-साथ राज्य सरकार के लिये भी राजस्व हितैषी हों।

हरियाणा के 10 ज़िलों में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की तर्ज पर खोले जाएंगे इनोवेटिव स्किल स्कूल

चर्चा में क्यों ?

11 जनवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के 10 ज़िलों में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की तर्ज पर इनोवेटिव स्किल स्कूल खोले जाने के लिये सहमति दी।

प्रमुख बिंदु

- इस उच्च स्तरीय बैठक में कौशल विकास विभाग के अधिकारियों ने विस्तार से स्किल इनोवेटिव स्कूल से संबंधित प्रारूप रखा और रोज़गार के निमित्त इनकी उपयोगिता का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया।
- स्किल एजुकेशन के केजी टू पीजी मॉडल और नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इन स्कूलों को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय संचालित करेगा। इसमें विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गए मॉडल को लागू किया जाएगा।
- सभी ज़िलों में स्कूल स्तर पर स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री ने केजी से पीजी तक स्किल एजुकेशन के मॉडल को लागू करने के निर्देश दिये हैं।
- श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश में सबसे पहले शुरू किये गए इनोवेटिव स्किल स्कूल की तर्ज पर प्रदेश के सभी ज़िलों में इनोवेटिव स्किल स्कूल खोले जाएंगे। इसके माध्यम से नई शिक्षा नीति के अनुसार केजी से पीजी तक स्किल एजुकेशन के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकेगी।

नोट :

- स्कूल स्तर पर स्किल एजुकेशन शुरू किये जाने से कई लक्ष्य एक साथ पूरे होंगे। इससे न केवल ड्रॉपआउट कम होगा, बल्कि ग्रॉस एजुकेशन रेशो (जीईआर) को भी बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही साथ उद्योग को कुशल मानवीय संसाधन मिलेंगे, जो गुणवत्ता और उत्पाद को बढ़ाने में सहायक साबित होंगे।
- नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति में स्किल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन के सामंजस्य का मॉडल सुझाया गया है। यह राष्ट्र, समाज और उद्योग की दृष्टि से आदर्श है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ऐसे सभी स्कूलों का संचालन करेगा और नवाचार की श्रेणी में सीबीएसई उन्हें मान्यता देगा।
- स्किल इनोवेटिव स्कूल खुलने के बाद रोज़गार के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। इसके माध्यम से विद्यार्थी स्कूल एजुकेशन के दौरान ही कौशल की तरफ आकर्षित होंगे और उच्चतर शिक्षा में भी वोकेशनल तथा स्किल एजुकेशन के प्रति रुझान बढ़ेगा।
- स्किल सेट में आईटी, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्यूटी वेलनेस, डिजाइन मेकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैंडीक्राफ्ट्स, मास मिडिया, हेल्थ केयर, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, फूड प्रोडक्शन व सिक्योरिटी जैसे विषय शामिल हैं।

जी-20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकों की मेजबानी हरियाणा को मिली

चर्चा में क्यों ?

12 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली के हरियाणा भवन में जी-20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि भारत की अध्यक्षता में हो रही जी-20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकों की मेजबानी हरियाणा को मिली है। इस ऐतिहासिक मेजबानी के लिये हरियाणा ने तैयारी भी शुरू कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पहली बार जी-20 ग्रुप की बैठकों की अध्यक्षता कर रहा है। इस सम्मेलन में 30 राष्ट्रों के अलावा 5 आमंत्रित सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि जी-20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकें गुरुग्राम में मार्च में आयोजित होनी प्रस्तावित हैं और इसकी सफलता के लिये सभी प्रबंध समय पर सुनिश्चित किये जाएंगे ताकि भारत की 'अतिथि देवो भव'के साथ हरियाणा की समृद्ध संस्कृति की अमिट छाप और गुरुग्राम-एक ग्लोबल सिटी का संदेश भी सभी जी-20 सदस्य देशों में जाए।
- उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जी-20 सदस्य देशों के शिष्टमंडल की सुविधा हेतु लायजन ऑफिसर लगाए जाएँ साथ ही, संभावित बैठकों के स्थल व उसके आस-पास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किये जाएँ। इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये आयोजन स्थल के पास अस्पतालों को भी चिह्नित करें।
- मुख्यमंत्री ने हैरिटेज एवं पर्यटन विभाग व सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभिन्न देशों के शिष्टमंडल का हरियाणा में आगमन होगा तो उन्हें राज्य की संस्कृति व विरासत से परिचय करवाने हेतु विशेष प्रबंध किये जाएँ।
- आयोजन स्थल पर हरियाणा थीम कॉर्नर भी स्थापित किया जाए, जहाँ मेहमानों के लिये हरियाणा के विकास गाथा से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो और साथ ही सांस्कृतिक विरासत की झलकियाँ भी उन्हें देखने को मिल सके।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला भी आयोजित होने वाला है। जी-20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को भी इस मेले में आमंत्रित किया जाएगा। इस मेले के माध्यम से सभी मेहमानों को न केवल हरियाणा बल्कि देश-विदेश के कलाकारों की कलाकृतियाँ, हथकरघा, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक ताने-बाने की समृद्धि और विविधता देखने को मिलेगी। इस कार्य में गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाएगा।
- उन्होंने बैठक में बताया कि जी-20 बैठकों के लिये सुरक्षा व्यवस्था के लिये पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था, एडीजीपी सीआईडी, पुलिस आयुक्त गुरुग्राम और गुरुग्राम के उपायुक्त इस टास्क फोर्स के सदस्य हैं।
- रेजिडेंट कमिश्नर, हरियाणा भवन दिल्ली की अध्यक्षता में एक प्रोटोकॉल समिति बनाई गई है और अतिरिक्त आवासीय आयुक्त हरियाणा, पुलिस आयुक्त गुरुग्राम के प्रतिनिधि, उपायुक्त और मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी गुरुग्राम इस समिति के सदस्य हैं।

नोट :

- कार्यक्रमों के दौरान हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिये सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशक और अतिरिक्त निदेशक, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग को सम्मिलित कर एक सांस्कृतिक समिति बनाई गई है।
- इसके अलावा बैठकों और कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान लॉजिस्टिक सहायता के लिये एक लॉजिस्टिक एवं परिवहन समिति भी बनाई गई है।

हरियाणा में महाराष्ट्र की तर्ज पर काम करेगी यातायात पुलिस

चर्चा में क्यों ?

13 जनवरी, 2023 को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य सरकार राज्य में सड़क दुर्घटनाएँ रोकने के लिये महाराष्ट्र की तर्ज पर पुलिस प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है, इसलिये राज्य में यातायात पुलिस की व्यवस्था बदली जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राज्य में आईजी ट्रैफिक ने महाराष्ट्र की तर्ज पर एसपी स्तर के अधिकारियों की यातायात पुलिस में तैनाती करने का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सड़क दुर्घटनाएँ रोकने के लिये महाराष्ट्र की तर्ज पर पुलिस प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी।
- गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि वर्तमान में हरियाणा की यातायात व्यवस्था बहुत ढीली चल रही है। राज्य सरकार ने आईजी ट्रैफिक का पद तो बना दिया लेकिन आईजी ट्रैफिक के पास शक्तियाँ न के बराबर हैं। आईजी एक एसएचओ का तबादला भी नहीं कर सकते। एसएचओ और डीएसपी ज़िले में पुलिस अधीक्षकों के अधीन आते हैं। पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से ही आईजी को निर्देश देने पड़ते हैं।
- उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था को लेकर जो खाका तैयार किया गया है उसके तहत आईजी ट्रैफिक इंचार्ज होगा। पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को यातायात पुलिस में लगाया जाएगा। एक एसपी के अंतर्गत चार या पाँच ज़िले रहेंगे। ज़िलों में ट्रैफिक डीएसपी कार्यरत होंगे। इन डीएसपी के अधीन एसएचओ ट्रैफिक होगा।
- विदित है कि हरियाणा में बीते वर्ष 2022 में 9951 सड़क दुर्घटनाओं में 4516 व्यक्तियों की जान गई और 8447 व्यक्ति घायल हुए हैं। परिवहन विभाग ने 2023 में 20 फीसदी दुर्घटनाएँ कम करने का लक्ष्य रखा है।
- दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये परिवहन विभाग सभी ज़िलों के लिये रोड सेफ्टी एसोसिएट्स अनुबंध आधार पर नियुक्त करेगा। राज्य सरकार ने सड़कों पर मार्किंग करने के निर्देश दिये हैं। ट्रैक्टर ट्राली आदि वाहनों पर रिफ्लेक्टर और लावारिस पशुओं की सींगों पर रिफ्लेक्टिव टेप जल्द से जल्द लगाने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत रोगियों को 25 गंभीर बीमारियों के लिये उपलब्ध करवाई जाएगी आर्थिक सहायता

चर्चा में क्यों ?

15 जनवरी, 2023 को हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने गरीब व्यक्तियों को इलाज के लिये तुरंत प्रभाव से लाभ मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिये 'मुख्यमंत्री राहत कोष योजना' में संशोधन किया है। अब 3 बीमारियों के इलाज के स्थान पर करीब 25 बीमारियों के इलाज के लिये पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करवाई जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थी सरल पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि आवेदक अपनी पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिये आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिये आवेदन कर सकते हैं।

नोट :

- मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में किये गए बदलावों के तहत यदि कोई बीमारी 'आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना'में कवर नहीं हो रही है तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
- मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिये ज़िला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित सांसद, संबंधित एमएलए, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, ज़िला परिषद के चेयरमैन, पंचायत समिति के चेयरमैन को सदस्य और नगराधीश को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
- प्रवक्ता ने बताया कि आवेदक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये जब सरल पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन करेगा, उसके बाद आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष ज़िला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर, एमसी के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा और ये जनप्रतिनिधि पाँच दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ उपायुक्त कार्यालय को भेजेंगे। उसके उपरांत आवेदन को उपायुक्त कार्यालय द्वारा संबंधित तहसीलदार को आवेदक की चल-अचल संपत्ति की वेरिफिकेशन तथा सिविल सर्जन को मेडिकल दस्तावेजों के सत्यापन के लिये भेजा जाएगा।
- उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिये इस पूरी प्रक्रिया में संपत्ति की वेरिफिकेशन के लिये चार दिन व सिविल सर्जन कार्यालय से जुड़े सत्यापन कार्य के लिये पाँच दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।
- उपरोक्त दोनों विभागों से मिली रिपोर्ट्स को उपायुक्त की संस्तुति के साथ कमेटी के सदस्य सचिव को भेजा जाएगा, जिसे वे सीनियर अकाउंट अधिकारी को भेजेंगे। इसके बाद स्वीकृत की गई राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेज दी जाएगी।

सरस्वती महोत्सव-2023

चर्चा में क्यों ?

15 जनवरी, 2023 को हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने बताया कि राज्य में सरस्वती महोत्सव-2023 का आयोजन 25 जनवरी को यमुनानगर ज़िले के आदिबद्री व 26 जनवरी को कुरुक्षेत्र ज़िले के पिहोवा के सरस्वती तीर्थ पर किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने बताया कि सरस्वती महोत्सव-2023 की शुरुआत आदिबद्री सरस्वती कुंड में 21 कुंडीय हवन यज्ञ से होगी, जिसको यादगार बनाने के लिये तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं।
- उन्होंने बताया कि इस महोत्सव का आयोजन बसंत पंचमी को लेकर किया जाता है। इस महोत्सव का शुभारंभ आदिबद्री सरस्वती उद्गम स्थल से किया जाएगा।
- धुमन सिंह किरमच ने बताया कि हवन यज्ञ के साथ श्लोक एंव मंत्रोच्चारण के कार्यक्रम के साथ ही बच्चों की पेंटिंग व ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। इस प्रतियोगिता की थीम भी सरस्वती पर आधारित होगी।

प्रदेश की सभी एयर-स्ट्रिप्स पर एटीएस और फायर-सिस्टम लगाए जाएंगे

चर्चा में क्यों ?

17 जनवरी, 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में 'डेवलपमैंट इंटीग्रेटिड एविएशन हब'की समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश की सभी एयर-स्ट्रिप्स पर एटीएस (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) और फायर-सिस्टम लगाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिनके पास नागरिक उड्डयन विभाग का प्रभार भी है, ने एयर-स्ट्रिप्स पर एटीएस (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) और फायर-सिस्टम लगाने के अतिरिक्त हैंगर बनाये जाने के भी निर्देश दिये ताकि एयर स्ट्रिप्स पर प्लेन सुरक्षित खड़े हो सकें।
- दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हिसार एयरपोर्ट के अंदर से होकर गुजरने वाली सड़क को बंद किया जाएगा, ताकि एयरपोर्ट की बाउंड्री-वॉल और पुराने रनवे को नए रनवे से जोड़ने के लिंकेज-कार्य को अंजाम दिया जा सके। स्थानीय लोगों की मांग पर एयरपोर्ट के बाहर से वैकल्पिक रोड बना दिया गया है, ताकि लोगों को आने-जाने में सुविधा रहे।

नोट :

- उन्होंने बताया कि 'डेवलेपमेंट इंटीग्रेटिड एविएशन हब'के कार्य में तेजी लाने के लिये जेई, एसडीओ समेत अन्य उच्चाधिकारियों की वहाँ स्थायी नियुक्ति की जा रही है, ताकि निर्धारित समय में काम को पूरा किया जा सके।
- इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव के स्तर पर हर पखवाड़ा कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, ताकि निर्धारित अवधि में कार्य संपन्न हो सके।
- उपमुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग के अन्य प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के बारे में बताया कि प्रदेश की करनाल की एयर-स्ट्रिप्स के वर्तमान 1000 मीटर के रनवे को 2000 मीटर तक बढ़ाने के लिये तकनीकी संभाव्यता जाँचने के निर्देश दिये गए हैं।
- इस एयर-स्ट्रिप्स पर लाइटें लगी हुई हैं, रनवे बढ़ाने पर दिल्ली की नाइट-लैंडिंग भी यहाँ पर हो सकेगी। करनाल में ही टर्मिनल-बिल्डिंग बनाने के लिये भी प्लानिंग की जा रही है।
- उन्होंने बताया कि भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल, पिंजौर आदि एयर-स्ट्रिप्स पर अतिरिक्त हैंगर लगाने के निर्देश दिये गए हैं, ताकि प्लेन सुरक्षित खड़े हो सकें।

हरियाणा पुलिस और आईआईएम रोहतक के बीच हुआ समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों ?

18 जनवरी, 2023 को हरियाणा पुलिस ने अपने अधिकारियों में प्रबंधकीय कौशल विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हरियाणा प्रशांत कुमार अग्रवाल और निदेशक आईआईएम रोहतक, प्रो. धीरज पी. शर्मा की उपस्थिति में पुलिस मुख्यालय में यह एमओए साइन हुआ।
- इस एमओए पर हरियाणा पुलिस की ओर से एडीजीपी (कानून व्यवस्था) हरियाणा, संदीप खिरवार और आईआईएम रोहतक से डॉ. शिवेंद्र कुमार पांडे, डीन (अनुसंधान और कार्यकारी शिक्षा) ने हस्ताक्षर किए।
- एमओए के अनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक और हरियाणा पुलिस संयुक्त रूप से एक पाठ्यक्रम विकसित करने और राज्य पुलिस के आईपीएस और डीएसपी रैंक के ग्रुप-ए के अधिकारियों के लिये प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा आयोजित करने का प्रस्ताव है। साथ ही, विशेष रूप से पुलिसिंग अनुप्रयोगों के लिये डिजाइन किये गए डेटा एनालिटिक्स में एक एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट प्रोग्राम आयोजित करने का भी प्रस्ताव है।
- इस समझौते के तहत पुलिस के काम और नागरिकों की अपेक्षाओं के बीच तालमेल बनाने के तौर-तरीकों को भी तलाशा जाएगा। राज्य सरकार पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिये पुलिस अधिकारियों को नामित करेगी। यह समझौता पाँच साल की अवधि के लिये प्रभावी होगा।
- एमओए का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों और आईआईएम-रोहतक के फैकल्टी व छात्रों के बीच नॉलेज-शेयरिंग के लिये एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना, क्षमता निर्माण और कौशल विकास में राज्य पुलिस की सहायता करना और मानद या परामर्श के आधार पर शैक्षणिक व शोध उद्देश्यों के लिये फैकल्टी और शोधार्थियों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना है।
- इस समझौते का उद्देश्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रभावी मानव संसाधन और सामग्री संसाधन प्रबंधन के लिये प्रबंधकीय कौशल प्रदान करना है।
- यह समझौता हरियाणा पुलिस को मामलों की जाँच की गुणवत्ता में और सुधार लाने, रिकॉर्ड के कुशल प्रबंधन और मामलों के प्रभावी पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिये नवीनतम तकनीकी हस्तक्षेपों के साथ पुलिस कर्मियों को अपडेट करने में सक्षम करेगा। वार्षिक संगोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशाला, अल्पावधि पाठ्यक्रम आदि भी इस एमओए का हिस्सा होंगे।

नोट :

संस्कृत साहित्यकारों की सम्मान राशि में बढ़ोत्तरी

चर्चा में क्यों ?

18 नवंबर, 2023 को हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉ. दिनेश शास्त्री ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा संस्कृत विद्वानों और साहित्यकारों के लिये बढ़ाई गई सम्मान राशि पर वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा सम्मान की नियमावली में भी फेरबदल किया गया है। सर्वोच्च सम्मान संस्कृत साहित्यालंकार और हरियाणा गौरव के लिये अब आयु सीमा का बंधन हटा दिया गया है। छात्रवृत्ति, अनुदान और वित्तीय सहायता योजना की राशि में भी कई गुना बढ़ोतरी की गई है।
- संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉ.दिनेश शास्त्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अकादमी द्वारा संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार एवं संवर्द्धन हेतु विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जाती हैं।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने फरवरी 2022 में आयोजित राज्य स्तरीय साहित्य पर्व के समय सम्मान राशि में वृद्धि करने की घोषणा की थी। इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया था। इसे मुख्यमंत्री द्वारा तीन माह पूर्व अनुमोदित कर दिया गया था। इसी कड़ी में प्रदेश के वित्त विभाग ने भी पुरस्कार की राशि वृद्धि पर स्वीकृति की मोहर लगा दी है।
- इससे इस बार से आवेदन करने वाले साहित्यकारों को इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत सम्मान राशि में दो गुना से लेकर साढ़े 3 गुना की बढ़ोतरी की गई है।
- डॉ. दिनेश शास्त्री ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के सम्मान 'संस्कृत साहित्यालंकार सम्मान' में पहले 2 लाख रुपए की राशि मिलती थी, इसे अब सीधा साढ़े तीन गुना बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह 'हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान'की पुरस्कार राशि दो लाख से सीधे ढाई गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है।
- इसी तरह महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास सम्मान की राशि डेढ़ लाख से ढाई गुना बढ़ाकर तीन लाख कर दी गई है। महर्षि विश्वामित्र सम्मान में डेढ़ लाख की जगह ढाई लाख , आचार्य स्थाणु दत्त सम्मान में अब डेढ़ लाख की जगह दो लाख रुपए मिलेंगे।
- इसी क्रम में महाकवि बाणभट्ट सम्मान में एक लाख की जगह ढाई लाख रुपए मिलेंगे। साहित्यकार सम्मान राशि पहले 11 लाख थी जो अब बढ़कर 25 लाख हो गई है।
- डॉ. दिनेश शास्त्री ने बताया कि आचार्य सम्मान में भी पुरस्कार राशि 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। इसके तहत अब गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान, विद्यामार्तंड पं.सीताराम शास्त्री आचार्य सम्मान, पं.युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान में अब एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे। स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधक सम्मान को भी एक लाख से दो लाख रुपए कर दिया गया है।
- डॉ. दिनेश शास्त्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने संस्कृत की नवलेखन प्रतिभाओं के लिये पुस्तक पुरस्कार राशि को भी 31 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 51 हज़ार रुपए कर दिया है। इससे साहित्य लेखन में प्रतिभाएँ और उत्साहपूर्वक कार्य करेंगी।
- पांडुलिपि प्रकाशनार्थ सहायता अनुदान में मानदेय राशि 10 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 21 हज़ार रुपए कर दी गई है। लघु संस्कृत कथा लेखन, नाटक लेखन प्रतियोगिता में प्रथम को अब 10 हज़ार, द्वितीय को 8 हज़ार तथा तृतीय को 5 हज़ार रुपए का पुरस्कार मिलेगा।
- डॉ. दिनेश शास्त्री ने बताया कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को भी सरकार ने विशेष तोहफा दिया है। इसके तहत प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, विशारद, प्राक् शास्त्री और शास्त्री कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति राशि अब तीन हज़ार की जगह 8 हज़ार रुपए मिलेगी।
- इसी तरह आचार्य कक्षाओं के छात्रों को 10 हज़ार रुपए मिला करेंगे। डॉ. दिनेश शास्त्री ने बताया कि अभावग्रस्त संस्कृत लेखकों को चिकित्सा खर्च में एक वर्ष में तीन हज़ार की जगह 50 हज़ार की सहायता मिल सकेगी। इसी तरह लेखक को वित्त वर्ष में मिलने वाली वित्तीय अनुदान राशि को भी बढ़ाकर 6 हज़ार से सीधे 21 हज़ार रुपए कर दिया गया है।

नोट :

हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिये लिंक अधिकारी किये नामित

चर्चा में क्यों ?

18 जनवरी, 2023 को हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यों के सुगम संचालन हेतु विभिन्न अधिकारियों को लिंक अधिकारी के रूप में नामित किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा पत्र जारी किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इन लिंक अधिकारियों में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव का प्रथम लिंक अधिकारी हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक होगा और हरियाणा बीज विकास निगम के प्रबंध निदेशक द्वितीय लिंक अधिकारी होंगे।
- इसी प्रकार, हरियाणा कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक का प्रथम लिंक अधिकारी कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के निदेशक होंगे।
- हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड, पंचकूला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रथम लिंक अधिकारी हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
- प्रबंध निदेशक, हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, गनौर का प्रथम लिंक अधिकारी हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का प्रबंध निदेशक होगा।
- हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रथम लिंक अधिकारी हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड, पंचकूला का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबंध निदेशक का प्रथम लिंक अधिकारी प्रबंध निदेशक, हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, गनौर होगा।
- मुख्य सचिव ने बताया कि आईएएस, एचसीएस अधिकारियों की अनुपस्थिति में विभागों, बोर्डों, निगमों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिये उनके अवकाश, प्रशिक्षण, दौरे, चुनाव ड्यूटी पर होने या स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त या किसी अन्य कारण से 2 दिनों से अधिक के लिये बाहर रहने की स्थिति में संबंधित लिंक अधिकारियों द्वारा कार्य देखा जाएगा। प्रत्येक अधिकारी छुट्टी, प्रशिक्षण, दौरे, चुनाव ड्यूटी पर जाने से पूर्व लिंक अधिकारी को सूचित करेगा।

'हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल' लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

19 जनवरी, 2023 को हरियाणा परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह वीर्क ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई 'हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल' लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह वीर्क ने बताया कि 'हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल'पढ़ने से सड़क उपयोगकर्त्ता को सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी और वह सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा को सुरक्षित बना सकेगा।
- उन्होंने बताया कि वाहनों के चालानों से प्राप्त आय के 50 प्रतिशत राशि को सड़क सुरक्षा के लिये प्रयोग करने का प्रावधान 2018 में जारी नियमों में किया गया है। लीड एजेंसी/परिवहन विभाग के द्वारा संबंधित विभागों से इन नियमों के अंतर्गत सड़क सुरक्षा से संबंधित योजनाएँ/स्कीमें मांगी जाती है।
- पिछले वर्ष 37 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसे पुलिस, परिवहन, शिक्षा, स्थानीय निकाय विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों/स्कीमों हेतु वितरित किया गया है।
- नवदीप सिंह वीर्क ने बताया कि सड़क सुरक्षा विषय को और अधिक विस्तार बनाने और नए पहलूओं को लाने की ज़रूरत है। सड़क सुरक्षा परिषद् की पिछले महीने हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिन राजमार्गों पर अवैध कट बनाए गए हैं, संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए।

नोट :

- इसी की पालना में सभी ज़िला परिवहन अधिकारियों को एक राष्ट्रीय राजमार्ग और एक राज्य राजमार्ग का चयन करके संबंधित विभागों से कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए हैं।
- उन्होंने बताया कि विभिन्न सड़कों की स्पीड लिमिट निर्धारित करने के संबंध में आईआईटी, मद्रास के साथ करार किया गया है, जिसके तहत वे इस संबंध में राज्य का सर्वेक्षण करेंगे और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देंगे।
- इसके अतिरिक्त, राज्य में परिवहन मंत्रालय द्वारा स्थापित आईरैड पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे सड़क पर होने वाली दुर्घनाओं और ब्लैक स्पॉट्स का पता चल सकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वाहन और सारथी पोर्टल द्वारा 22 फेसलैस सेवाएँ शुरू की गई हैं, जिससे सेवा का अधिकार अधिनियम अनुसार ऑनलाईन आवेदन से तय समय पर सुविधाएँ दी जाएंगी।
- विदित है कि हरमन सिंह सिद्धु ने इस मैनुअल को तैयार किया है और इस मैनुअल की अंग्रेजी भाषा में 10,000 प्रतियाँ सीएसआर फंड से तैयार करने का कार्य मारूति कंपनी के कार्यकारी निदेशक राहुल भारती ने किया है।
- इसी तरह से हिन्दी भाषा में इस मैनुअल की 5,000 प्रतियाँ मारूति कंपनी तैयार करके देगी, जिसे रोड सेफटी नॉलेज सैंटर्स और ड्राईविंग स्कूलों/प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जाएगा।
- परिवहन आयुक्त यशेंद्रा सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा एक गंभीर विषय है जिसमें सभी विभागों तथा जनता की भागीदारी अति आवश्यक है जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। इसके लिये यह मैनुअल बहुत उपयोगी साबित होगा और इसको पढ़ने से ड्राइविंग सीखने वालों और लाईसेंन्स बनवाने वालों तथा आम जनता को सड़क सुरक्षा के बारे में नियमों की जानकारी मिलेगी और सड़क दुघर्टनाओं को कम किया जा सकेगा।
- इस अवसर पर हरमन सिंह सिधू ने बताया कि तत्कालीन परिवहन आयुक्त अमिताभ ढिल्लो के मार्गदर्शन में इस सड़क सुरक्षा मैनुअल को तैयार किया गया है।
- इस मैनुअल को चार भागों में बाँटा गया है, जिसमें भाग-1 में सड़क आघात व प्रमुख जोखिम कारक, भाग-2 में अपने वाहन को जानने जिसमें टायर, ब्रेंक, स्टेयरिंग, व्हील, रोशनी, विंड स्क्रीन, रियर व्यू मिरर, हार्न, ब्लाइंड स्पॉट्स को जानना, सड़कों के नियम, सुरक्षित ड्राइविंग, अन्य सड़क उपयोगकर्त्ताओं के प्रति विनम्र ड्राईविंग करना व सुरक्षित ड्राइविंग, भाग-3 में उचित दूरी पर गाड़ी चलाना, दूरियों का पालन करना, आपातकालीन वाहनों के बारे में, चौराहों पर यातायात सिंग्नलों का पालन करते हुए ड्राईविंग करना, सिग्नल के प्रकार, मार्क का अधिकार, संकेत देने, लेन बदलने, हाईवे ड्राइविंग, ओवरटेकिंग, रेलवे क्रासिंग, विभिन्न परिस्थितियों में ड्राईविंग, गाड़ी रोकने, पार्क करने व सड़क चिन्हों तथा भाग-4 में आपातकालीन स्थिती और दुर्घटनाएँ, सड़क सांझा करना, दुर्घटना पीड़ित की मदद करना, गुड समारटियन की मद्द करना, पर्यावरण के प्रति जिम्मेवारी और कानून इत्यादि के बारे में बताया गया है।

हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 54वीं बैठक

चर्चा में क्यों ?

19 जनवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 54वीं बैठक हुई, जिसमें उन्होंने वर्ष 2026 तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है।

प्रमुख बिंदु

- सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में 528 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। खेतों में खड़े पानी की निकासी और पानी के दोबारा इस्तेमाल के लिये 312 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएँ अनुमोदित की गई हैं।
- हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि राज्य के जिन इलाकों में जलभराव की अधिक समस्या है, उसके स्थायी समाधान के लिये इस वर्ष विशेष प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे।
- इसके अलावा, जल संरक्षण और बरसात के पानी का दोबारा उपयोग करने के लिये भी अधिक से अधिक ज़ोर दिया जा रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति से निपटने के साथ-साथ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग व सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी का सदुपयोग किया जा सकेगा।

नोट :

- इस बार जलभराव की निकासी के लिये क्लस्टर एप्रोच के माध्यम से योजनाएँ तैयार की गई हैं। भिवानी ज़िले को एक क्लस्टर माना गया है, जिसके तहत 8 गाँवों कुंगड़, जटाई, धनाना, बढेसरा, सिवाड़ा, प्रेमनगर, घुसकानी, ढाणी सुखन के आबादी एरिया व जलभराव वाले इलाकों में एचडीपीई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस पर लगभग 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी। इससे लगभग 2 हज़ार एकड़ जलभराव वाली भूमि से पानी की निकासी होगी।
- इसके अलावा, 3 गाँवों सिंघवा खास, पुठ्ठी, मदनहेड़ी को मिलकार एक योजना बनाई गई है, जिस पर 31 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इससे लगभग 1500 एकड़ जलभराव वाली भूमि से पानी की निकासी होगी। इसी प्रकार, लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत की एक ओर योजना बनाई गई है, जिसके क्रियान्वित होने से 885 एकड़ जलभराव वाली भूमि से पानी की निकासी होगी।
- उन्होंने बताया कि ज़िला हिसार को क्लस्टर मानकर 3 गाँवों भाटोल जाटान, रांगड़ान और खरकड़ा के खेतों से पानी की निकासी के लिये 20 करोड़ रुपए की योजना अनुमोदित की गई है। इससे लगभग 750 एकड़ जलभराव वाली भूमि का सुधार होगा।
- इसके अलावा, खरबला गाँव के लिये भी 50 करोड़ रुपए की योजना को भी अनुमोदित किया गया है। ज़िला रोहतक के लिये भी अलग से योजनाओं को मंज़ूरी दी गई है।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जहाँ बहुत ज्यादा जलभराव होता है, ऐसी भूमि पर झीलें बनाई जाए। विशेषकर एनसीआर ज़िलों में लगभग 100 झीलें बनाने की एक योजना तैयार की जाए।
- इन झीलों के बनने से जलभराव की समस्या का भी स्थायी सामाधान होगा और भू-जल रिचार्जिंग की क्षमता भी बढ़ेगी। इन झीलों को बनाने के लिये किसानों से उनकी जलभराव वाली भूमि के प्रस्ताव मांगे जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि जल की उपलब्धता वर्तमान समय में एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिये जल संरक्षण ही एक मात्र समाधान है। इसी दिशा में भू- जल रिचार्जिंग के लिये सरकार द्वारा ज़िलों में रिचार्जिंग बोरवेल लगाए जा रहे हैं।
- उन्होंने बताया कि इस दिशा में एक कदम ओर आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर रिचार्जिंग बोरवेल लगा सकता है। इन बोरवेल पर सरकार पैसा खर्च करेगी और किसानों से भी कुछ सहयोग लिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि 54वीं बैठक में विभिन्न श्रेणियों के तहत योजनाएँ बनाई गई हैं। इसमें जल संरक्षण और पानी के पुन: उपयोग के लिये 97 योजनाओं पर करीब 179 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी।
- इसके अलावा आबादी प्रोटेक्शन श्रेणी की 67 योजनाओं पर 41 करोड़ रुपए, प्रोटेक्शन आफ एग्रीकल्चर लैंड श्रेणी में 125 योजनाओं पर 132.86 करोड़ रुपए, डीवॉटरिंग मशिनरी श्रेणी में 49 योजनाओं पर 77.90 करोड़ रुपए, रिक्लेमेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड श्रेणी की 68 योजनाओं पर 119.50 करोड़ रुपए तथा रिकंस्ट्रक्शन, ड्रेनों में पानी के समुचित बहाव के लिये मरम्मत व नए स्ट्रक्चर बनाने के लिये 59 योजनाओं पर 110 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है।
- इसी प्रकार हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण तथा अटल भूजल योजना के तहत 63 योजनाओं पर 167 करोड़ रुपए की राशि मंज़ूरी की गई है।
- बैठक के बाद मनोहर लाल ने बताया कि आम तौर पर 10 ज़िलों नामत: रोहतक, झज्जर, भिवानी, हिसार, जींद, फतेहाबाद, सोनीपत, कैथल, पलवल और सिरसा में जलभराव की समस्या देखने को मिलती है। इसलिये इन 10 ज़िलों में विशेष फोकस देते हुए बैठक में अधिकतर योजनाएँ इन्हीं ज़िलों के लिये अनुमोदित की गई हैं।
- उन्होंने बताया कि साल में दो बार जनवरी और मई माह में हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक होनी तय की गई है। मई माह में जनवरी की बैठक में तय किये गए छोटी अवधि के प्रोजेक्ट और दीर्घकालीन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जाएगी।
- जल संरक्षण और पानी के दोबारा उपयोग के लिये भी पिछली बार के 35 करोड़ रुपए के बजट को 167 करोड़ रुपए तक बढ़ाया है।
- उन्होंने बताया कि आबादी और कृषि क्षेत्र में जमा हो रहे पानी को ड्रेन आउट करने की बजाय रिचार्ज करने पर बल दिया जा रहा है। 50 एकड़ से ज्यादा एरिया में पानी खड़ा होता है, वो ज़मीन सरकार लेने को तैयार है। उस जगह पर तालाब या रिचार्ज वेल बनाने का काम किया जाएगा।

नोट :

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 86 बेटियों को किया जाएगा पुरस्कृत

चर्चा में क्यों ?

19 जनवरी, 2023 को हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बताया कि हर साल 24 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश में 86 बेटियों को 6 लाख 24 हज़ार 9 सौ रुपए की राशि एवं प्रशंसा-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बेटियों के कल्याणार्थ चलाई गई विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप उन्हें आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेटियों ने भी अनेक उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करने वाली बालिकाओं को प्रशंसा-पत्र व इनामी राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि खेलकूद, शिक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने पर बालिकाओं को 11-11 हज़ार रुपए की राशि व बालिकाओं की राज्य स्तर पर हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को 5100, 2100 तथा 1100 रुपए की राशि और प्रशंसा-पत्र दिये जाएंगे।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी की बैठक

चर्चा में क्यों ?

21 जनवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कुल 92 करोड़ रुपए से अधिक की वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- एचपीपीसी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में सिंचाई, पुलिस, परिवहन, हारट्रॉन, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कुल 8 एजेंडा रखे गए थे, जिसमें से 5 एजेंडे को मंजूरी दी गई।
- उन्होंने बताया कि विभिन्न कंपनियों से नेगोशिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 3 करोड़ रुपए को बचत की गई है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि थर्मल पावर प्लांट में प्रदूषण को कम करने के लिये डी-नॉक्स कंब्यूशन कॉंडिफिकेशन सिस्टम लगाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है। इसके अलावा हरियाणा में विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये भी आज मंज़ूरी प्रदान की गई है।
- उन्होंने बताया कि सरकारी परियोजनाओं के लिये भूमि की आवश्यकता हेतू ई-भूमि पोर्टल बनाया गया है, जो बेहद कारगर साबित हो रहा है। इस पोर्टल पर सरकार की ओर से परियोजनाओं के लिये ज़मीन की आवश्यकता की जानकारी भरी जाती है और किसान तथा एग्रीगेटर्स अपनी ज़मीन का ऑफर देते हैं।
- भू-मालिकों से बातचीत कर उनकी सहमति से ज़मीन खरीदी जा रही है। अब तक लगभग 1000 एकड़ भूमि की खरीद इस पोर्टल के माध्यम से की गई है।

गणतंत्र दिवस समारोह के लिये हरियाणा की झाँकी का थीम होगा 'अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव'

चर्चा में क्यों ?

22 जनवरी, 2023 को हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिये लगातार दूसरी बार हरियाणा की झाँकी का चयन रक्षा मंत्रालय की विषेशज्ञ कमेटी द्वारा किया गया है, जिसका थीम है- 'अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव'।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व मंत्रालयों की झांकियों के चयन की प्रक्रिया नवंबर माह में शुरू की जाती है, जिसमें सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व मंत्रालय अपने-अपने थीम की प्रस्तुति देते हैं।
- विशेषज्ञ कमेटी द्वारा थीम की प्रासंगिकता व उपादेयता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से झांकियों का चयन किया जाता है। पिछले वर्ष भी 'खेलों में नंबर वन हरियाणा'की थीम पर आधारित झाँकी के माध्यम से हरियाणा की खेल उपलब्धियों को सशक्त तरीके से देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया था।
- उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र को दुनिया के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पवित्र नदी सरस्वती के तट पर वेदों और पुराणों की रचना हुई। लगभग 5159 वर्ष पहले महाभारत युद्ध के पहले दिन भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का शाश्वत संदेश दिया, इसलिये कुरुक्षेत्र की पहचान गीता के जन्म स्थल के रूप में होती है।
- डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि गीता के अमर संदेश की जयंती की वर्षगांठ को कुरुक्षेत्र में हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 18 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्देश्य श्रीमद्भगवद्गीता के वैश्विक व प्रेरणादायक संदेश का प्रसार करना और दुनिया को शांति, सद्भाव तथा सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश से आलोकित करना है।
- उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में हरियाणा सरकार ने दुनिया के अन्य हिस्सों में गीता के सनातन संदेश को फैलाने के उद्देश्य से अन्य देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाने का निर्णय लिया और वर्ष 2019 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मॉरीशस व लंदन में आयोजित किया गया। वर्ष 2022 में कनाडा में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया।
- सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक ने बताया कि गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झाँकी पर प्रस्तुत गीता का संदेश मानवजाति के लिये सबसे बड़ी बौद्धिक देन है। कर्म का यह शाश्वत संदेश पूरी मानवता के लिये अनुकरणीय है।
- उन्होंने बताया कि झाँकी में भगवान श्रीकृष्ण को अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते हुये और उन्हें गीता का ज्ञान देते हुए दिखाया गया है। झाँकी की पहली झलक आध्यात्मिकता, कला और इतिहास के दर्शन कराती है।
- ट्रैक्टर खंड की शुरुआत में भगवान श्रीकृष्ण के 'विराट स्वरूप' के दर्शन होते हैं, जैसा कि युद्ध भूमि पर उन्होंने अर्जुन के सामने प्रदर्शित किया था। विराट स्वरूप की प्रदर्शित प्रतिमा में श्री विष्णु के 9 सिर क्रमश: अग्नि, नृसिंह, गणेश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, हनुमान और परशुराम दिखाए गए हैं। दिव्य सर्प सिर ढके हुए हैं। श्री विष्णु दाहिने हाथ में तलवार, त्रिशूल, कमल, सुदर्शन चक्र और बाएँ हाथ में शंख, बरछा, धनुष, नाग, गदा आदि लिये हुए हैं। नीचे का पूरा भाग शेषनाग व लहरों को गोलाकार आकार दिया गया है।
- ट्रेलर अनुभाग में पीछे की ओर कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में चार घोड़ों के साथ एक भव्य रथ बनाया गया है। रथ, घोड़ों और सभी तत्त्वों को गहन विवरण के साथ दर्शाया गया है। अर्जुन और श्रीकृष्ण के रथ पर सवार मूर्तियों को रंगीन बनाया गया है, जबकि ट्रेलर के बाकी हिस्से को एक ही पार्थिव छाया में बनाया गया है। झाँकी में घोड़ों से लेकर रथ तक और यहाँ तक कि जमीन की धूल भी, हर एक विवरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ट्रेलर के किनारों पर बना पैटर्न महाभारत युद्ध के विभिन्न दृश्यों को दर्शाता है।

इंडो-इजराइल कृषि परियोजना के तहत गिगनाऊ में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

22 जनवरी, 2023 को भारत में आए इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने हरियाणा के भिवानी ज़िले के लोहारू विधानसभा क्षेत्र के गाँव गिगनाऊ में साढ़े 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करीब 50 एकड़ भूमि में बने अर्द्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने बताया कि गाँव गिगनाऊ में इंडो-इजराइल कृषि परियोजना के तहत स्थापित बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के बीच लोकतांत्रिकों संबंधों को भी मज़बूती देगा।
- अर्द्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नए संसाधनों को विकसित करना है, जिससे किसान खुशहाल हो।

नोट :

- उन्होंने बताया कि अब इजराइल की तकनीक व जानकारी भारत में स्थानांतरित व निर्मित की जा रही है, जिससे मेक इन इंडिया पहल को और अधिक बढावा मिल रहा है। इस केंद्र के माध्यम से भारत में उत्पादित इजराइल आधारित कृषि तकनीक जैसे ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, ग्रीन हाऊस आदि का प्रदर्शन किया जाएगा।
- नाओर गिलोन ने बताया कि भारत में इंडो-इजराइल तकनीक पर निर्मित बागवानी उत्कृष्टता केंद्रों में गुणवत्ता वाली सब्जी की चार करोड़ से अधिक पौध व गुणवत्ता वाले फलों के पाँच लाख पौधे तैयार किये जा रहे हैं। इन केंद्रों पर हर साल एक लाख 20 हज़ार से अधिक किसानों को प्रशिक्षण भी मिल रहा है।
- हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जे.पी दलाल ने बताया कि इजराइल एक छोटा सा देश होते हुए भी कृषि व सुरक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में अग्रणी है। आज इस देश की तकनीक को दूसरे देश भी अपना रहे हैं। इजराइल ने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर अपने देश को स्वर्ग बनाया है तथा पूरी दुनिया को बूँद-बूँद से खेती करने की तकनीक दी है।
- उन्होंने बताया कि हरियाणा में बागवानी के बजट को 100 गुणा बढ़ाकर 8 करोड़ से 800 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रदेश में 500 एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- जे.पी दलाल ने बताया कि कि वर्ष 2030 तक 17 लाख एकड़ भूमि पर बागवानी का लक्ष्य रखा गया है। सोनीपत के गन्नौर में दुनिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी स्थापित की जा रही है, जो 500 एकड़ में होगी, जिस पर ढाई हज़ार करोड़ की लागत आएगी और इससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- उन्होंने बताया कि बागवानी में जोखिम को कम करने के लिये 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' लागू की गई है, इस योजना के तहत 46 फसलों को कवर किया गया है। इसके अलावा 'भावांतर भरपाई योजना' के तहत 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है।
- मंत्री जे.पी दलाल ने बताया कि देश में किसानों के लिये सबसे अधिक योजना हरियाणा में लागू की गई है। गिगनाऊ में बना उत्कृष्ट केंद्र किसानों के साथ-साथ युवाओं के भविष्य के लिये मील का पत्थर साबित होगा।
- इस सेंटर में अमरूद, बादाम, खजूर, अनार, नाशपाती, नींबू वर्गीय फल, बेर, ड्रैगन फ्रूट, रेड बल्ड माल्टा, स्ट्रॉबेरी, अवोकाडो आदि की उत्तम क्वालिटी की किस्म तैयार की जाएगी। इस केंद्र से किसानों को उच्च गुणवत्ता की सब्जियों की पौध सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी।
- इस हाइटेक ग्रीन हाउस में सब्जियों की 30 से 40 लाख तक पौध को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा फलों की पौध हेतु मदर ब्लॉक तैयार किये जा रहे हैं।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैदियों को मिलेगी तीन महीने तक की छूट

चर्चा में क्यों ?

24 जनवरी, 2023 को हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी है।

प्रमुख बिंदु

- ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 90 दिन और जिन अपराधियों को पाँच वर्ष से ऊपर व 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन की छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार, जिन अपराधियों को पाँच वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट प्रदान की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2023) पर कारागार से पैरोल और फरलोह पर आए सभी अपराधियों को भी यह छूट दी जाएगी, बशर्ते वे अपने निर्धारित समय पर संबंधित कारागार में आत्मसमर्पण कर देते हैं। उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में उन्हें यह छूट दी जाएगी।
- रणजीत सिंह ने बताया कि जिन अपराधियों पर जुर्माना भुगतान न करने पर सजा हुई है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी और जिन अपराधियों को हरियाणा में आपराधिक न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है लेकिन वे हरियाणा के बाहर जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, उन्हें उपरोक्त पैमाने के अनुसार यह छूट प्राप्त करने का अधिकार होगा। जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।

नोट :

- उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की हत्या तथा अपहरण, बलात्कार के साथ हत्या, डकैती और लूटपाट, टैरोरिस्ट एंड डिसरैप्टिव एक्टिविटीज (प्रीवेंशन) अधिनियम-1967, कार्यालय गोपनीय अधिनियम-1923, विदेशी अधिनियम-1948, पासपोर्ट अधिनियम-1967, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम-1961 की धारा 2 और 3, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 121 से 130, फिरौती के लिये किडनैपिंग, पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत कोई अपराध, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत धारा 32ए के तहत सजा काट रहे अपराधियों को छूट नहीं दी जाएगी।
- जेल मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान नेशनल, अपराध दंड सहिंता 1973 की धारा 107/109/110 की धाराओं के साथ-साथ शांति बनाए रखने के मामले में सुरक्षा देने में असफल होने वाले अपराधिक व्यक्ति, पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी बड़े जेल अपराध में संलिप्त अपराधियों के मामले में सजा काट रहे अपराधियों को पंजाब जेल मैनुअल, हरियाणा जेल नियम-2022 या उस दिन लागू किसी अन्य अधिनियम या नियमों के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी।

प्रदेश के दो विभूतियाँ पद्म श्री सम्मान के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

25 जनवरी, 2023 को राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2023 के लिये देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों 'पद्म पुरस्कारों'की घोषणा की। इनमें हरियाणा की दो विभूतियों को पद्म श्री अवार्ड के लिये चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2023 के लिये, राष्ट्रपति ने तीन द्वय मामलों (एक द्वय मामले में, पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है) सहित 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंज़ूरी दी है।
- सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएँ हैं और विदेशियों/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई की श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं।
- पद्म पुरस्कार के लिये चयनित हरियाणा की दो विभूतियों में बक्शी राम और डॉ. सुकामा आचार्या शामिल हैं।
- झज्जर ज़िले के अकुपुर गाँव की डॉ. सुकामा आचार्या को अध्यात्मवाद के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये और गुरुग्राम के कृषि वैज्ञानिक डॉ. बख्शी राम को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये पद्म श्री अवार्ड के लिये चुना गया है।
- कृषि वैज्ञानिक डॉ. बख्शी राम को गन्ने की किस्म CO-0238 विकसित करने के लिये जाना जाता है।
- गौरतलब है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार शामिल है। पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों- पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के रूप में प्रदान किये जाते हैं। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है।
- यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में दिये जाते हैं।
- असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म विभूषण', उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म भूषण'और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये 'पद्म श्री'से सम्मानित किया जाता है।
- ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोहों में प्रदान किये जाते हैं जो आमतौर पर हर साल मार्च/अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किये जाते है।

दीनबंधु छोटूराम के जयंती समारोह में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएँ की

चर्चा में क्यों ?

25 जनवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के कुरुक्षेत्र ज़िले की जाट धर्मशाला में आयोजित किसानों के मसीहा दीनबंधु सर छोटूराम के जयंती समारोह में कई घोषणाएँ की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने के रेट में 10 रुपए इज़ाफा करते हुए 372 रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने पटवारियों के वेतन को 25 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 32100 रुपए करने का भी ऐलान किया।
- उन्होंने बताया कि पाले की वजह से सरसों की फसल का काफी नुकसान हुआ है, ऐसे में फसल की गिरदावरी करवाई जाएगी और किसानों को मुआवज़ा दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने जाट धर्मशाला के लिये 51 लाख रुपए देने की भी बड़ी घोषणा की। जाट धर्मशाला द्वारा बनाए जाने वाले छात्रावास के लिये ज़मीन की व्यवस्था कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार संत-महापुरुष प्रचार प्रसार योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत संत-महापुरुषों की जयंतियाँ सरकारी तौर पर मनाई जाती है।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की डेढ़ लाख एकड़ भूमि में जल भराव की समस्या वाली भूमि को ठीक करने के लिये 1100 करोड़ रुपए का बजट अगले वर्ष तक खर्च किया जाएगा। इस भूमि को कृषि योग्य बनाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि दीनबंधु छोटूराम ने अपने आदर्शों पर काम करते हुए अंग्रेजो से टक्कर ली और गरीब व किसान के लिये कानून बनवाए। उन्होंने ही बाज़ारों, दुकानों व फैक्ट्री में सप्ताह में एक दिन की छुट्टी को लागू करवाया। दीनबंधु छोटूराम ने ही कर्ज में दबे किसानों को चंगुल से बाहर भी निकाला था।

हरियाणा-सस्केचेवान शैक्षणिक गोलमेज सम्मेलन का हुआ आयोजन

चर्चा में क्यों ?

25 जनवरी, 2023 को हरियाणा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विदेश सहयोग विभाग द्वारा राज्य के पंचकूला ज़िले में हरियाणा-सस्केचेवान शैक्षणिक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा-सस्केचेवान शैक्षणिक गोलमेज सम्मेलन में हरियाणा और सस्केचेवान के बीच शैक्षणिक व कौशल विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की पहचान, सुविधा, समर्थन, मजबूती पर चर्चा की गई।
- इस अवसर पर विदेश सहयोग विभाग के महानिदेशक एवं सचिव अनंत प्रकाश पांडे ने बताया कि हरियाणा सरकार कौशल विकास, शैक्षणिक अनुसंधान, छात्र व फैकल्टी अनुसंधान, पाठ्यक्रम विकास जैसे क्षेत्रों में सस्केचेवान के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिये प्रतिबद्ध है। इन प्रयासों को और सुदृढ़ करने के लिये सस्केचेवान पॉलिटेक्निक की विशेषज्ञता का लाभ लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने तेजली स्टेडियम के विकास के लिये की 90 करोड़ रुपए की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

26 जनवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर यमुनानगर ज़िले के जगाधरी में तेजली स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और ज़िला-वासियों को तेजली स्टेडियम का विकास करने की घोषणा करते हुए 90 करोड़ रुपए की सौगात दी।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि यमुनानगर ज़िले के तेजली स्टेडियम को आधुनिक रूप से 3 चरणों में विकसित किया जाएगा। 50 एकड़ में फैले इस स्टेडियम में इनडोर व आउटडोर गेम्स की सभी सुविधाएँ मिलेंगी।
- उन्होंने बताया कि पहले चरण में इंडोर खेल, जिनमें जूडो, कबड्डी, ताइक्वांडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, लॉन टैनिस, आर्चरी, राईफल शूटिंग आदि के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित व सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

नोट :

- अगले चरण में आउटडोर गेम्स को विकसित किया जाएगा, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, एथलैटिक्स, टेबल टैनिस, वॉलीबॉल, बास्केट बॉल, हैंडबाल, बैडमिंटन आदि खेल विकसित किये जाएंगे।
- यह कार्य खेल विभाग द्वारा किया जाएगा और लगभग 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा।

प्रदेश में 33 नए महिला पुलिस थाने और 239 महिला हैल्प डेस्क स्थापित

चर्चा में क्यों ?

26 जनवरी, 2023 को हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के अंबाला शहर स्थित पुलिस लाइन परिसर में 74वाँ गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बताया कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिये प्रदेश में 33 नए महिला पुलिस थाने और 239 महिला हैल्प डेस्क स्थापित किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य सरकार हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 15 प्रतिशत करने के लिये कृत-संकल्प है। इसी कड़ी में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिये 'दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स'की 24 कंपनियाँ स्कूल-कॉलेज जाने वाली छात्राओं व अन्य महिलाओं की सुरक्षा के लिये तैनात की गई हैं।
- उन्होंने बताया कि लोगों को एफ.आई.आर. दर्ज करवाने में दिक्कत न आए, इसके लिये जीरो एफ.आई.आर. की अवधारणा शुरू की गई है। अब किसी भी थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा सकती है, चाहे घटना कहीं भी घटित हुई हो।
- गृह मंत्री ने बताया कि करनाल ज़िले के मधुबन स्थित पुलिस कॉम्पलैक्स में फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला (एफ.एस.एल) में ट्रैकिया बार-कोडिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। यह सिस्टम पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत है। थाने के स्तर से लेकर फौरेंसिक लैब तक इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
- उन्होंने बताया कि पासपोर्ट सत्यापन निश्चित समय अवधि से पहले भेजने के लिये हरियाणा पुलिस को 5 बार पुरस्कृत किया गया है।
- अनिल विज ने बताया कि अंबाला रेंज में 5 तथा करनाल ज़िले के मूनक में एक नया पुलिस थाना खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। लोगों में पुलिस सुरक्षा का भाव बढ़े और पुलिस उनके साथ हर कदम पर है, इसके दृष्टिगत 112 टोल फ्री नंबर के तहत पुलिस के बेड़े में 600 गाड़ियाँ जोड़ी गई हैं। हर थाने में दो-दो गाडियाँ मुहैया करवाई गई हैं।

यूआईईटी के दो छात्रों का स्मार्ट सोलर हब हुआ लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

25 जनवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्च्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (यूआईईटी) के दो छात्रों इशांक बंसल और अर्जुन मित्तल द्वारा शुरू किये गए स्मार्ट सोलर हब स्टार्टअप को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने सोलर एनर्जी के इनविनोवा नाम के इस स्टार्ट-अप को लॉन्च किया है।
- उन्होंने बताया कि स्टार्टअप के मामले में हरियाणा का देश में तीसरा स्थान है। 60 हज़ार नई स्टार्टअप कंपनियों में से पाँच हज़ार कंपनियाँ हरियाणा में हैं, जोकि 12 प्रतिशत हैं।
- डॉ. अग्रवाल ने बताया कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत अलग-अलग प्रकार की छूट व रियायतें देकर प्रदेश में नए स्टार्टअप स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- स्मार्ट सोलर हब नाम से शुरू किये गए स्टार्टअप इनविनोवा का उद्देश्य एक्सेसीबल एनर्जी और कनेक्टीविटी के साथ आउटडोर स्पेस में सार्वजनिक इंटरेक्शन को बढ़ाना है।

नोट :

- इसके माध्यम से सार्वजनिक जीवन में टेक्नोलॉजी को लोकप्रिय बनाकर अर्बन लिविंग को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर फोकस किया गया है। शहरों को ज़्यादा जीवंत, सस्टेनेबल और ज़्यादा संवेदनशील बनाने में भी यह टेक्नोलॉजी कारगर सिद्ध होगी।
- इस अवसर पर पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रो. वाई.पी वर्मा ने बताया कि यूआईईटी में कुल 8 स्टार्टअप चल रहे हैं, जिनके लिये विभाग जगह देता है और ज़रूरी उपकरण उपलब्ध कराता है।

हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारी पुलिस पदक से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

26 जनवरी, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों व कर्मियों को विशिष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक से अलंकृत किया गया।

प्रमुख बिंदु

- घोषित किये गए कुल 14 पदकों में से एक पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा 13 अन्य को सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।
- पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अमिताभ सिंह ढिल्लों, पुलिस महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण) को विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिये चुना गया है।
- जिन्हें सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है, उनमें - सतेंद्र कुमार गुप्ता आईजीपी (करनाल रेंज) करनाल, बी. सतीश बालन आईजीपी (एसटीएफ), वीरेंद्र कुमार विज डीसीपी (ईस्ट) गुरुग्राम, सुरेंद्र सिंह डीएसपी (सीआईडी) नई दिल्ली, राजकुमार रंगा एसीपी पंचकूला, हरि किशन इंस्पेक्टर स्टेट क्राइम ब्रांच, रमेश कुमार सब-इंस्पेक्टर (एसआई) अंबाला, दिनेश सिंह एसआई प्रथम आईआरबी भोंडसी गुरुग्राम, नरेश कुमार एसआई रोहतक, देवेंद्र कुमार एएसआई पानीपत, राम पाल ईएएसआई (सीआईडी) चंडीगढ़, सज्जन कुमार ओआरपी एएसआई हिसार और सुनील कुमार हेड कॉन्स्टेबल पंचकूला शामिल हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुप्तिसागर नेचर केयर इंस्टीट्यूट का किया शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

29 जनवरी, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गन्नौर स्थित श्री 108 गुप्तिसागर धाम जैन ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र गुप्तिसागर नेचर क्योर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने श्री 108 गुप्तिसागर जी महाराज द्वारा अंत्योदय प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी खान-पान की आदतें ठीक हों, शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिये आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा अहम है। प्राकृतिक चिकित्सा कोई चिकित्सा नहीं, बल्कि पद्धतियों का सार है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा के नाते आयुष्मान भारत योजना क्रियान्वित की गई है, उसी तर्ज़ पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा में 'चिरायु हरियाणा योजना' शुरू की है और इसके तहत हरियाणा में 29 लाख परिवार 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा का लाभ सूचीबद्ध अस्पतालों व नागरिक अस्पतालों में उठा सकते हैं।

कुरुक्षेत्र के किरमिच गाँव से हुई प्रधानमंत्री मोदी की 'मन की बात' कार्यक्रम की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

29 जनवरी, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल पहली बार 'मन की बात' कार्यक्रम के 97वें एपिसोड की शुरुआत हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गाँव किरमिच से की। इसमें प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज पैदा करने से लेकर लोकतंत्र को और प्रगाढ़ किये जाने, ई-वेस्ट से बेस्ट निकालने सहित कई अहम संदेश दिये।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि इस बार 'मन की बात' कार्यक्रम से हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा व उत्तर प्रदेश सीधेतौर पर जुड़े। इसमें हरियाणा से एकमात्र गाँव किरमिच के बूथ नंबर 180 कालू पट्टी से किसान धुम्मन सिंह का चयन किया गया था।
- कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस समारोह में की गईं कई नई पहल को लेकर देश भर में की जा रही सराहना की चर्चा की तो वहीं मोटे अनाज को लेकर इंटरप्योर बने लोगों के उदाहरण भी दिये।
- प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज पर विशेषतौर पर चर्चा की, जो हरियाणा की प्रमुख खेती है। इससे किसानों का हौंसला बढ़ा है। उनके इस संदेश से मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा।
- उल्लेखनीय है कि 'मन की बात' आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसके ज़रिये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नागरिकों को संबोधित करते हैं। इस कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्तूबर, 2014 को किया गया था। जनवरी 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उनके साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया था तथा भारत की जनता के पत्रों के उत्तर दिये थे।
- जुलाई 2021 में राज्यसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री के एक बयान के अनुसार, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 'दिन-प्रतिदिन के शासन के मुद्दों पर नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करना' है। यह कार्यक्रम भारत का 'पहला नेत्रहीन समृद्ध रेडियो कार्यक्रम' है।

स्वास्थ्य विभाग व हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित

चर्चा में क्यों ?

30 जनवरी, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 5 से अधिक सेवाओं तथा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण की 3 सेवाओं की निर्धारित समयसीमा अधिसूचित की है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ (पहले से पंजीकृत) चालू वर्ष के लिये 14 दिन, गत वर्षों 1972 तक के लिये 30 दिन और 1972 से पूर्व के मामले में 90 दिन की समयसीमा तय की गई है।
- इसी प्रकार बालक के नाम का पंजीकरण के लिये 30 दिन, जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि का शुद्धिकरण (पूर्ण आवदेन प्रस्तुतीकरण के बाद) के लिये 30 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है।
- इसके अलावा, अनुवांशिक काउंसलिंग केंद्र, अनुवांशिकी प्रयोगशालाएँ, अनुवांशिकी क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केंद्र का नया पंजीकरण तथा क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग केंद्र के पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने के लिये 90 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है।
- मुख्य सचिव ने बताया कि जन्म और मृत्यु घटनाओं का विलंबित पंजीकरण के तहत आवेदक घटना के 21 दिन के पश्चात् किंतु 30 दिन के अंदर आवेदन करता है तो 21 दिन की समयसीमा, घटना के 30 दिन के पश्चात् किंतु एक वर्ष से पूर्व के मामले में 30 दिन की समयसीमा, घटना घटित होने के एक वर्ष के पश्चात् लेकिन 1972 तक 60 दिन की समयसीमा तथा 1972 से पूर्व के लिये 90 दिन की समयसीमा निर्धारित की है।
- उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण द्वारा बीज उत्पादन के लिये फर्म का पंजीकरण, बीज के संसाधन के लिये संसाधन संयंत्र का पंजीकरण तथा बीजों के संसाधन के लिये संसाधन संयंत्र का नवीकरण के लिये समयसीमा 21 दिन निर्धारित की गई है।

नोट :

जॉर्जिया और हरियाणा विभिन्न विषयों पर करेंगे सहयोग

चर्चा में क्यों ?

30 जनवरी, 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम ज़िले में जॉर्जिया के भारत में राजदूत आर्चिल जुलियाश्विली ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर हरियाणा और जॉर्जिया के बीच कई विषयों पर सहयोग के बारे में चर्चा की। इनमें मुख्यत: कृषि, मेडिकल एजुकेशन, हैल्थ सिस्टम, फार्माश्युटिकल और स्पोर्ट्स शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- जॉर्जिया के राजदूत आर्चिल जुलियाश्विली ने हरियाणा सरकार द्वारा आई टी क्षेत्र में किये गए सफल प्रयोग को लेकर रुचि दिखाते हुए बताया कि जॉर्जिया हरियाणा की इस पहल से सीखना चाहता है कि किस प्रकार आईटी के प्रयोग से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाई जा सकती है।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में की गई आईटी पहलों की जानकारी देते हुए बताया कि आईटी के प्रयोग से सरकारी कार्यों में जहाँ एक ओर पारदर्शिता लाने में मदद मिली है वहीं दूसरी ओर सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचाया जा रहा है।
- जॉर्जिया के राजदूत आर्चिल ने हरियाणा से अपने देश में योग को बढ़ावा देने के लिये सहयोग की मांग भी की है। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सहयोग का आश्वासन दिलाते हुए बताया कि विदेश सहयोग विभाग इस संबंध में एक फ्रेमवर्क बनाकर देगा कि किस प्रकार से हरियाणा जॉर्जिया को सहयोग दे सकता है।

The Vision

नोट :